

बिहार सरकार  
अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग  
सं०-४ / निदे०पी०सी०आर०(विधि)०२-१२-१३ / २०१५- १५५

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,  
निदेशक।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी  
बेगूसराय।

पटना-15, दिनांक- 29.03.17

विषय: वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन कुल ₹ 5.00 लाख (पाँच लाख रु०) मात्र का पुर्नवांटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना(50:50) के तहत विभागीय पत्रांक-08 दिनांक-29.04.2016 द्वारा बजट उपबन्ध के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹5,00,00,000/- (पांच करोड़ रु०) एवं राज्यांश मद में ₹5,00,00,000/- (पांच करोड़ रु०) अर्थात् कुल ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रु०) मात्र की स्वीकृति दी गई है। जिसके आलोक में पत्रांक-17 दिनांक-06.06.16 द्वारा केन्द्रांश मद में ₹3,15,00,000/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) एवं राज्यांश मद में ₹3,15,00,000/- (तीन करोड़ पन्द्रह लाख) अर्थात् कुल ₹6,30,00,000 ( छः करोड़ तीस लाख) मात्र की राशि आवंटित की गई है।

2- उपरोक्त आवंटित राशि में से जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर के पत्रांक 139 दिनांक-17.03.2017 द्वारा अनु० जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 के तहत गठित अनु० जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमावली-1995 एवं संशोधन नियम-2014 तथा नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में व्यय के आवंटित राशि में से कुल ₹1139326/- (ग्यारह लाख उनचालीस हजार तीन सौ छब्बीस रु०) मात्र का प्रत्यापण प्राप्त हुआ है। जिसे स्वीकार किया जाता है।

3- उपरोक्त प्रत्यापित राशि में से वित्तीय वर्ष-2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना अन्तर्गत अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के अधीन जिला कल्याण पदाधिकारी, बेगूसराय के पत्रांक-516 दिनांक-27.03.17 के मॉग के आलोक में केन्द्रांश मद में ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रु०) एवं राज्यांश मद में ₹2,50,000/- (दो लाख पचास हजार रु० ) अर्थात् कुल ₹500000/- (पाँच लाख रु०) मात्र पुर्नवांटित किया जाता है।

4- इस राशि के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी होंगे, जो निकासी की गई राशि की व्यय की विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग होंगे।

5- इस राशि से अनु० जाति और अनु० जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, संशोधन अधिनियम-2015, नियम-1995 एवं (संशोधन) नियम-2016 एवं नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 के धाराओं और नियमों के प्रावधानों के तहत अनु० जाति एवं अनु० जनजाति के पीडित व्यक्तियों को अत्याचार से राहत अनुदान की राशि अनुसूची और उपबन्ध-1{नियम-12(4)} में राहत राशि के लिए मापदण्ड के साथ-साथ नियम-12(4)(21) में मुख्य रूप से हत्या, मृत्यु, नरसंहार, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, स्थायी असमर्थता और डकैती के मामलों में पीडितों को भुगतान की जाने वाली राहत राशि के अतिरिक्त अत्याचार की तिथि से मृतक की प्रत्येक विधवा और/या अन्य आश्रितों को प्रति मास की दर से पेंशन भुगतान किया जाएगा साथ ही अधिनियम के तहत (i) पीडित/पीडिता को वैधिक सहायता, (ii) पीडित/पीडिता को यात्रा भत्ता, (iii) पीडित/पीडिता को दैनिक भत्ता, (iv) पीडित/पीडिता को राहत और पुनर्वास (v) प्रचार-प्रसार (vi) जागरूकता (vii) पुलिस महानिरीक्षक (क०व०) के अधीन अनु० जाति और अनु० जनजाति संरक्षण कक्ष, (viii) सर्वेक्षण इत्यादि पर व्यय की स्वीकृति दी जा सकेगी।

6- राशि की स्वीकृति के तुरंत बाद ही जिला पदाधिकारी द्वारा अत्याचार राहत हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता और फौजदारी मुकदमा के संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना सरकार के पास विस्तारपूर्वक अपने मन्तव्य के साथ भेजेंगे। साथ ही उक्त प्रतिवेदन की एक प्रति प्रधान सचिव, गृह विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

7- केन्द्रांश के लिए राशि मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष-“2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0218-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3302-मुआवजा विपत्र कोड सं०-P2225012770218” तथा राज्यांश के लिए मांग सं०-44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष- “2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0318-अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम-विषय शीर्ष-3302-मुआवजा, विपत्र कोड सं०-P2225012770318” से विकलनीय है।

8- इन मदों के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक-2561 दिनांक-17.4.98 तथा समय समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

9- इस आवंटन के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यय की गई राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र दिनांक-31-04-2017 तक विभाग को भेजेंगे एवं महालेखाकार से लेखा का सत्यापन कराकर प्रतिवेदन भेजेंगे।

10- इस आवंटन की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिश्वासभाजन ,

(वीरेन्द्र कुमार) 31/17  
निदेशक।

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)02-12-13/2015- 144 पटना, दिनांक- 29.03.17  
प्रतिलिपि : 1-महालेखाकार, बिहार/वित्त विभाग, बजट शाखा/योजना एवं विकास विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2- प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग/पुलिस महानिरीक्षक (क० व०) अपराध अनुसंधान विभाग बिहार पटना।

3- प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत एवं मुंगेर /जिला पदाधिकारी, शिवहर/उप विकास आयुक्त, शिवहर एवं बेगूसराय / प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण, तिरहुत एवं मुंगेर/अवर सचिव, प्रभारी, बजट शाखा, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सहायक निदेशक, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/ जिला कल्याण पदाधिकारी, शिवहर एवं बेगूसराय/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक। 31/17

ज्ञापांक-4/निदे०पी०सी०आर०(विविध)02-12-13/2015- 144 पटना, दिनांक- 29.03.17  
प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, बेगूसराय/शिवहर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक। 31/17